

## यूरो क्षेत्र के संकट का दक्षिण एशिया पर प्रभाव\*

दीपक मोहंती

यूएस में उत्पन्न वैश्विक मौद्रिक संकट बाद में यूरोप तक फैल गया। हालांकि, वैश्विक संवृद्धि 2009 के झटके से उबर चुकी है, तथापि यूरोप फिर से मंदी के जाल में फंस गया है। यूरो क्षेत्र की सतत अनिश्चितता आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने बड़ा जोखिम उपस्थित कर रही है। इसने व्यापार, वित्तीय और विश्वास माध्यमों के जरिये उन्नत और उभरती दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं की संवृद्धि दर पर विपरीत असर डाला है। वित्तीय बाजारों की अंतर-संबद्धता को देखते हुए उभरते बाजारों और विकासशील देशों का प्रमुख जोखिम वैश्विक वित्तीय बाजारों के “रिस्क ऑन” तथा “रिस्क-ऑफ” व्यवहार से उत्पन्न होता है। हाल में, कुछ नीतिगत उपायों से यूरो क्षेत्र में वित्तीय स्थितियों में सुधार आया है (आइएमएफ 2013)<sup>1</sup>। लेकिन, वास्तविक अर्थव्यवस्था में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है। राजकोषीय उपायों के लिए बहुत कम स्थान होने की वजह से गिरती संवृद्धि दर को उठाने के संबंध में समष्टि नीतिगत उपाय सीमित बने रहे।

यूरो क्षेत्र संकट 2009 में तब प्रकाश में आया जब पुर्तगाल, आयरलैंड, ग्रीस तथा स्पेन में मंदी दिखाई दी तथा बहुत अधिक बजट घाटा दिखाई दिया। यह संकट 2010 में तब और भी गहरा गया जब साख-निर्धारण एजेंसियों ने यूरोप की इन सरकारों की तथा वहां के बैंकों की रेटिंग घटा दी। इससे विश्वास को तो बड़ा झटका लगा ही, यूरो के अस्तित्व पर भी संकट दिखाई देने लगा।

इस परिप्रेक्ष्य में, मैं यूरो क्षेत्र में संकट के कारणों तथा वहां स्थिरता बढ़ाने के लिए किए गए नीतिगत उपायों पर चर्चा करूंगा। उसके बाद, मैं इस बात पर आऊंगा कि

\* इस्लामाबाद पाकिस्तान में 18 जून 2013 को आयोजित सार्कफाइनेंस समूह की बैठक में भारिबैं के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मोहंती द्वारा दिया गया भाषण। इस भाषण को तैयार करने में डा.महुआ रॉय तथा श्री सोमनाथ शर्मा का प्रशंसनीय योगदान रहा।

<sup>1</sup> आइएमएफ (2013), “ओल्ड रिस्क-न्यू चैलेंजेस,” वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अप्रैल 2013।

इस संकट ने दक्षिण एशिया को, विशेषकर भारत को कैसे प्रभावित किया। हमने अपने बाह्य खाते को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए, इस पर प्रकाश डालते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

### संकट के कारण

यूरो क्षेत्र की समस्याएं मुख्यतः ढांचे से संबंधित हैं तथा इस संकट से पहले भी मौजूद रही हैं। वैश्विक संकट ने सिर्फ प्रणाली की कमजोरियों को सामने लाने का काम किया है. “संकट के पूर्व के वर्षों में, यूरोप ऐसे देशों के दो समूहों में बंट गया जिनमें एक ओर वे देश थे जिनका व्यापार संतुलन सकारात्मक था और बजट की स्थिति भी अच्छी थी, वहीं दूसरी ओर वे देश थे जिनका बजट घाटा और बाह्य घाटा लगातार बढ़ रहा था और जिसका वित्तपोषण पहले समूह के देशों द्वारा दिये जाने वाले निजी ऋणों से अनुत्पादक व्यय के लिए किया जा रहा था। वैश्विक वित्तीय संकट के कारण जैसे ही शेष यूरोप द्वारा उक्त वित्तपोषण बंद कर दिया गया, दूसरे समूह के देशों का बाह्य घाटा, बजट घाटा और सार्वजनिक ऋण सामर्थ्य से परे होता गया (द्राघी 2013)”<sup>2</sup>।

यूरो क्षेत्र के संकट का मूल स्रोत बहुत अधिक राजकोषीय घाटा तथा ऋण रहा है। पहला, इन अर्थव्यवस्थाओं की कमजोर राजकोषीय स्थिति का बड़ा भाग बढ़ती उम्र के लोगों पर होने वाले उस व्यय से संबंधित है जिससे राजस्व में कोई वृद्धि नहीं होती। साथ ही, संवृद्धि बढ़ाने वाले ढांचागत सुधारों के अभाव के कारण भी यह स्थिति बनी है। इस प्रक्रिया में, सार्वजनिक क्षेत्र का ढांचा चरमरा गया। दूसरे, घरेलू बचत दर कम होने से सार्वजनिक ऋण की चुकौती उधार लेकर करनी पड़ी जिससे चालू खाता घाटे में तथा विदेशी ऋण में वृद्धि हुई। जबकि यूरो क्षेत्र की सदस्यता आसपास के देशों को झूठी आरामदायक स्थिति का अहसास कराती रही, वहीं अंतर-यूरो क्षेत्र के वित्तीय असंतुलन गंभीर बने रहे। तीसरे, यूरो क्षेत्र के संकट के अनसुलझे रहने पर सरकारों और बैंकों के बीच अंतर-संबद्धता, विशेषकर आसपास के देशों में, बैंक ऋणों के डिफाल्ट स्वेप स्प्रेड तथा सरकारों के बीच सकारात्मक सह-संबंध के रूप में प्रतिबिंबित हुई।

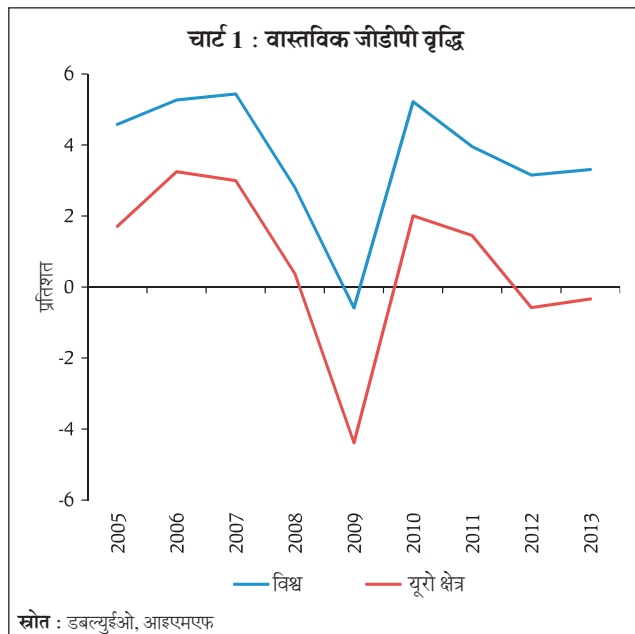
<sup>2</sup> द्राघी मारिओ (2013). “दि यूरो मोनेटरी पॉलिसी एंड रिफोर्स.” लुइस गुइडो कार्ली विश्वविद्यालय, रोम में 6 मई को राजनीति विज्ञान की मानार्थ उपाधि प्राप्त करते समय दिया गया भाषण।

यूरो क्षेत्र संकट का प्रबंधन तीन कारणों से जटिल बन गया है। पहला, रेटिंग कम होने के कारण, कई देशों को बांड संबंधी देयताओं के बढ़ने तथा सरकारी ऋण के निधियन की चुनौती का सामना करना पड़ा। दूसरे, यूरो क्षेत्र के बैंक, विशेषकर सरकारी बांडों में हुई हानि के कारण, कम-पूंजी का शिकार रहे तथा चलनिधि की कमी के कारण ऋण बाधा की समस्या से जूझते रहे।

### नीतिगत उपाय

इस संकट ने यूरोपीय संघ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में स्थिरता लाने के लिए कुछ कदम उठाने के लिए अभिप्रेरित किया। उक्त क्षेत्र में संकट की तात्कालिकता की वजह से 2010 में यूरोपीय वित्तीय स्थिरता सुविधा तथा 2011 में यूरोपीय वित्तीय स्थिरता तंत्र की स्थापना हुई। लेकिन, यूरोपीय वित्तीय स्थिरता तंत्र की स्थापना के लिए आधार बनने वाले बाद के कई सुधारों ने क्षेत्रीय वित्तपोषक व्यवस्थाओं को अधिक मजबूती प्रदान की।

इसके अलावा, यूरोपियन यूनियन धीरे-धीरे बैंकिंग तथा राजकोषीय यूनियन की ओर बढ़ कर मौद्रिक यूनियन की संस्थागत कमियों को दूर करने का भी प्रयास कर रहा है। यूरोप ने बैंकिंग यूनियन की ओर पहला बड़ा कदम दिसंबर 2012 में उठाया जब यूरोपियन यूनियन के वित्त मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि ईसीबी को कॉमन बैंक सुपरवाइजर बना दिया जाए।



यूरोपियन यूनियन ने राजकोषीय नियमों को और सख्त बनाने का प्रयास किया है। इस संबंध में, स्थिरता समन्वयन तथा अभिशासन संधि, जिसे फिस्कल कंपैक्ट के नाम से जाना जाता है, जनवरी 2013 में लागू की गई। यह सरकारों के बीच संधि है, जिसके अनुसार सभी सदस्य देशों को इस संधि की परिभाषा के भीतर अपने राष्ट्रीय बजटों को संतुलित करने या अधिशेष वाला बजट बनाने के लिए, वरीयतः संविधान स्तर पर कानून बनाना होगा। इस कानून में स्वतःसुधार व्यवस्था का भी प्रावधान होना चाहिए ताकि इसके उल्लंघन को रोका जा सके। इस संधि में संतुलित बजट ऐसे सामान्य बजट को माना गया है, जिसमें बजट घाटा जीडीपी के 3.0 प्रतिशत से कम हो तथा यदि ऋण स्तर 60 प्रतिशत से कम हो तो संरचनागत घाटा जीडीपी के 1.0 प्रतिशत से कम हो। यदि ऋण स्तर जीडीपी के 60 प्रतिशत से अधिक हो तो संरचनात्मक घाटे संबंधी मानदंड और भी सख्त अर्थात् जीडीपी का 0.5 प्रतिशत होगा। इस 'टू-पैक' विनियम में यूरो क्षेत्र के देशों से यह भी अपेक्षा की गई है कि वे अपनी बजट योजनाओं की पूर्व सूचना यूरोपियन कमीशन (ईसी) को दें। यदि संबंधित देश घाटा आधिक्य की प्रक्रिया अपनाते हैं या ईएसएम के किसी वित्तीय सहायता कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो ईसी उन पर और भी कड़ी निगरानी रख सकेगा (प्रेट 2013)<sup>3</sup>।

ईसीबी ने कई नीतिगत उपाय किए हैं, जिनमें नीतिगत ब्याज दर को कम करना, बड़ी बांड खरीद तथा बैंकों को रियायती दरों पर ऋण देना शामिल है। ईसीबी ने दीर्घावधि पुनर्वित्त परिचालन शुरू किए हैं जिसके अंतर्गत बैंकों को तीन-वर्षीय ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अंतर्गत दिसंबर 2011 में 523 बैंकों ने 489 बिलियन यूरो का तथा फरवरी 2012 में 800 बैंकों ने 530 बिलियन यूरो का ऋण लिया। ईसीबी ने सितंबर 2012 में पूर्णतः मौद्रिक लेनदेनों की शुरुआत की है ताकि ईएफएसएफ/ईएसएम के जरिये अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए संबंधित देश की पूर्व प्रार्थना पर अल्पकालीन सरकारी बांडों की विवेकाधीन खरीद की जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ईसी तथा ईसीबी के निकट सहयोग से ग्रीस, आयरलैंड तथा पुर्तगाल को आपात ऋण

<sup>3</sup> ईसीबी के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य पीटर प्रेट का भाषण। यूरो क्षेत्र में संकट पर प्रतिक्रिया : बीजिंग -17 अप्रैल 2013

दिया तथा उनके आर्थिक समायोजन कार्यक्रमों पर निगरानी भी रखी, जिसे “ट्रोइका” के नाम से जाना जाता है। इस सहायता का बड़ा भाग यूरो क्षेत्र के देशों से आया, लेकिन आइएमएफ से लिये गए उधारों की मात्रा भी काफी बड़ी थी। चूंकि इस बचाव पैकेज की राशि काफी बड़ी थी, अतः समस्त आपात निधियां सिर्फ आइएमएफ द्वारा उपलब्ध कराना संभव नहीं था। यही कारण था कि ईसी तथा ईसीबी से भी सहायता लेनी पड़ी। अब मैं यूरो क्षेत्र के संकट के सार्क क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव पर आता हूँ।

### दक्षिण एशिया क्षेत्र पर प्रभाव

यूरो क्षेत्र परंपरागत रूप से दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोगी रहा है। वर्ष 2012 में कुल निर्यातों में यूरो क्षेत्र को निर्यात में मालदीव का हिस्सा लगभग 38 प्रतिशत, नेपाल का 10 प्रतिशत तथा भारत का 13 प्रतिशत था। वर्ष 2011 से 2012 के बीच यूरो क्षेत्र को सार्क के निर्यातों के हिस्से में काफी कमी आई है (सारणी 1)।

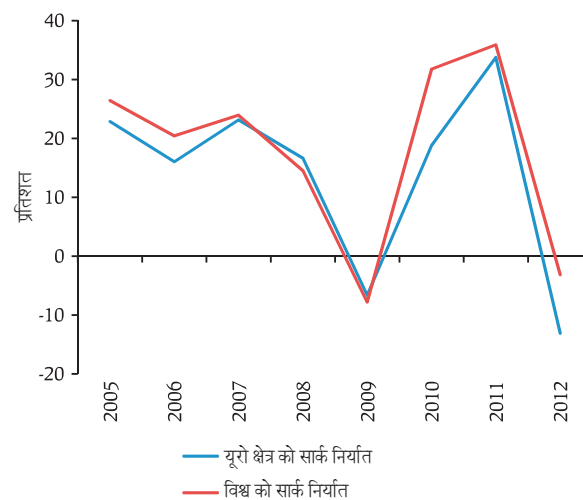
सारणी 1 : कुल निर्यातों में से यूरो क्षेत्र को निर्यात का प्रतिशत हिस्सा			
	2008	2011	2012
बांगला देश	36.4	35.7	32.2
भारत	16.1	13.9	12.8
मालदीव	29.6	37.7	37.8
नेपाल	8.6	10.8	9.7
पाकिस्तान	16.2	16.7	12.9
श्रीलंका	21.7	22.6	17.8

स्रोत : डीओटीएस, आइएमएफ आंकड़ों पर आधारित

सार्क क्षेत्र के निर्यातों में तो यूरो क्षेत्र का काफी बड़ा हिस्सा है ही, यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा पूंजी प्रवाह के अन्य रूपों में भी यूरो क्षेत्र को काफी योगदान देता है (ली एट अल.2013)<sup>4</sup>। यह जानना रोचक होगा कि जब 2010 में यूरो क्षेत्र के संकट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया तब उस क्षेत्र को हमारे निर्यातों में तत्काल कोई कमी नहीं आई। ऐसा हमारे दो प्रमुख व्यापारिक भागीदारों अर्थात्

<sup>4</sup> ली मिन्यू डोंगयू पार्क, अर्नेलिन एब्डोन तथा जेम्मा एस्ट्रेडा(2013), यूरो क्षेत्र के सरकारी ऋण संकट का विकासशील एशिया पर अर्थिक प्रभाव। एडीबी वर्किंग पेपर सीरीज नं. 336, जनवरी 2013।

चार्ट 2 : विश्व और यूरो क्षेत्र को दक्षिण एशिया के निर्यातों में परिवर्तन



स्रोत : आइएमएफएस, आइएमएफ

जर्मनी और फ्रांस के कारण हुआ जो अच्छा कर रहे थे। इसके बाद की अवधि में, जैसे ही संकट गहराया यूरो क्षेत्र को हमारे निर्यातों में गिरावट आई (चार्ट 2)।

यूरो क्षेत्र के संकट ने दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को वित्तीय माध्यम से भी प्रभावित किया है। यूरोपियन बैंक दक्षिण एशिया को ऋण का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक के अनुसार, दिसंबर 2012 के अंत में दक्षिण एशिया पर यूरोपियन बैंकों का समेकित दावा 164 बिलियन अमरीकी डालर का था, जो इस क्षेत्र पर विदेशी बैंकों के कुल दावे के 44 प्रतिशत के बराबर होता है। शेयर बाजारों के माध्यम से भी प्रभाव पड़ा है। जबकि उभरते बाजारों को यूरोपियन बैंकों के उधारों में कमी आई, वहीं निवेशकों के रुझान में परिवर्तन होने से उभरते शेयर बाजारों में निवेश प्रवाह में कमी आई (एवडिजएव एट एल.2012)<sup>5</sup>। अब मैं भारत पर इसके प्रभाव पर आता हूँ।

### भारत पर प्रभाव

भारतीय अर्थव्यवस्था यूरो क्षेत्र से काफी जुड़ी है। अब तक जो प्रभाव पड़ा है, वह मुख्यतः व्यापार और वित्त के माध्यम से हुआ है। यूरो क्षेत्र में गिरावट के परिणामस्वरूप, उस क्षेत्र को भारत के पण्य निर्यात 2011 के 42.7 बिलियन

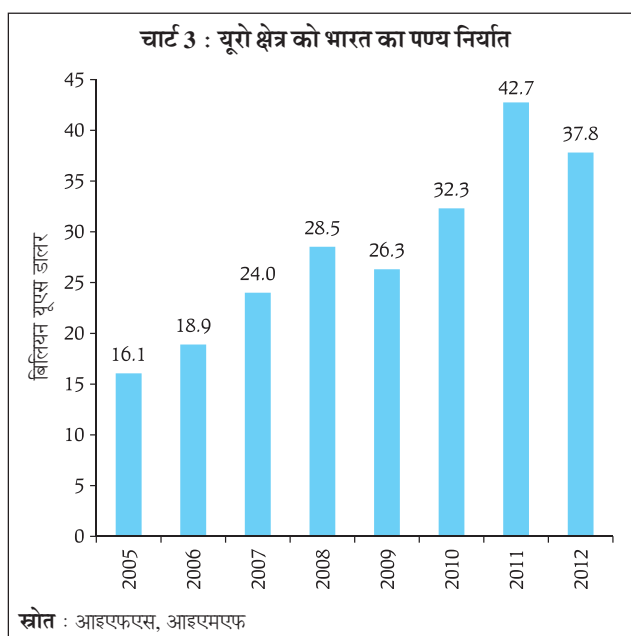
<sup>5</sup> एवडिजएव स्टीफन, जोल्ट कुट तथा एलोड टेकाट्स (2012). यूरो क्षेत्र संकट और उभरते बाजारों में देशों के बीच बैंक उधार। बीआइएस क्वार्टर्ली रिव्यू, दिसंबर 2012।

डालर से घट कर 2012 में 37.8 बिलियन अमरीकी डालर के रह गए (चार्ट 3)। इसके फलस्वरूप, भारत के कुल निर्यातों में इसका हिस्सा 13.9 प्रतिशत से घट कर 12.8 प्रतिशत रह गया। वास्तव में, भारत के निर्यातों में यूरो क्षेत्र का हिस्सा 2008 में इससे कहीं अधिक 16 प्रतिशत था (सारणी 1)।

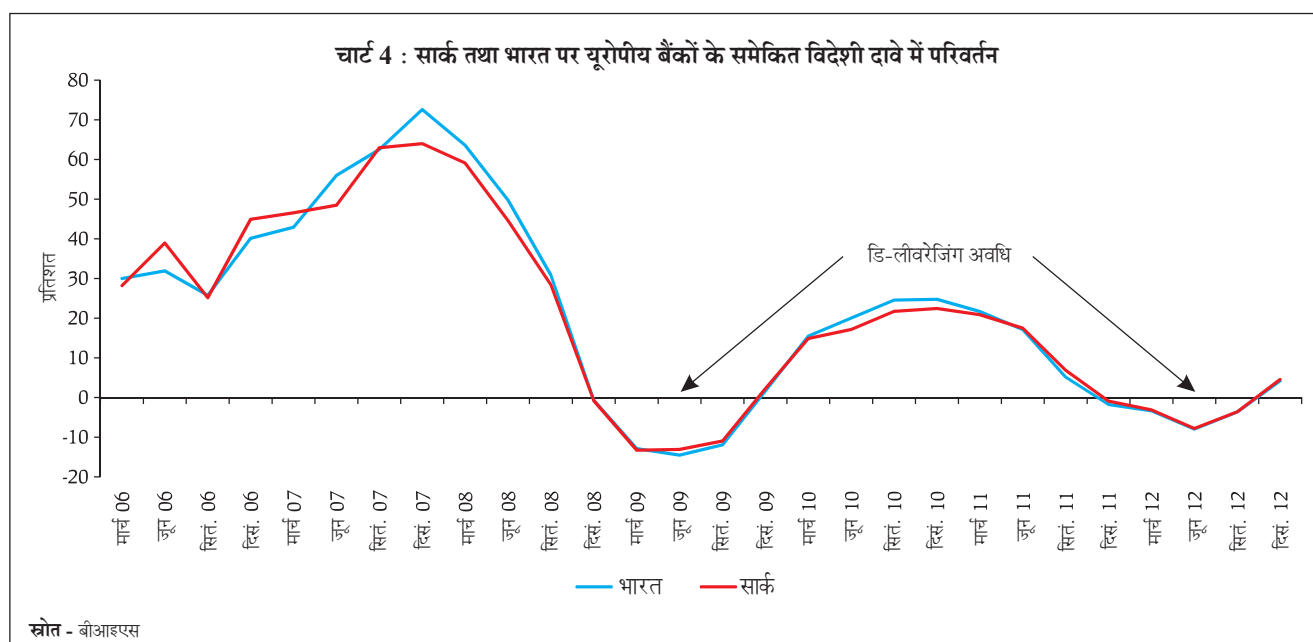
इसके अलावा, यूरोप को भारत के सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात में भी कमी आई, और यह 2009-10 की सॉफ्टवेयर निर्यात से कुल आय के 26 प्रतिशत से घट कर 2011-12 में 24 प्रतिशत रह गई। भारत में आने वाले कुल पर्यटकों में यूरोप का हिस्सा एक-तिहाई से ज्यादा है। यूरो क्षेत्र से, विशेषकर प्रभावित क्षेत्र से, कम पर्यटक आने के कारण यात्रा-प्राप्तियों में भी गिरावट आई।

यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली के डि-लीवरेजिंग से भारत को ऋण प्रवाह प्रभावित हुआ (चार्ट 4)। भारत पर यूरोपीय बैंकों का समेकित दावा दिसंबर 2010 के 146 बिलियन अमरीकी डालर से घट कर दिसंबर 2012 में 139 बिलियन डालर रह गया।<sup>6</sup>

यूरो क्षेत्र भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्ष 2012-13 में भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में इसका हिस्सा 18 प्रतिशत था। विदेशी संस्थागत निवेश प्रवाह के मुकाबले इन प्रवाहों का



स्वरूप अधिक स्थिर के कारण, भारत को एफडीआई प्रवाह पर संकट का बहुत कम प्रभाव पड़ा। जब संकट शुरू हुआ यूरो क्षेत्र से एफडीआई प्रवाह 2009-10 के लगभग 3.5 बिलियन अमरीकी डालर से घट कर 2010-11 में 3.1 बिलियन अमरीकी डालर रह गया। लेकिन, 2011-12 में इसमें सुधार हुआ और यह 4.2 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया, 2012-13 में यह 3.5 बिलियन अमरीकी डालर रहा (सारणी 2)।



<sup>6</sup> दिसंबर 2012 के अंत में, यूके और स्विट्जरलैंड को छोड़ कर भारत पर यूरोपीय बैंकों के दावे 56 बिलियन अमरीकी डालर के थे।

## सारणी 2 : भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह : देशवार

(बिलियन अमरीकी डालर)

कुल एफडीआइ	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
	22,461	14,939	23,473	18,286
देशवार प्रवाह				
साइप्रस	1,623	571	1,568	415
नीदरलैंड	804	1,417	1,289	1,700
जर्मनी	602	163	368	467
फ्रांस	283	486	589	547
स्पेन	125	183	251	348
लक्जमबर्ग	40	248	89	34
यूरो क्षेत्र (6)	3,477	3,068	4,154	3,511
कुल एफडीआइ में यूरो क्षेत्र (6) का हिस्सा	15.5	20.5	17.7	19.2

स्रोत - भारिबैं

इसके अलावा, यूरोप भारत को निजी अंतरण प्रवाह का भी एक प्रमुख स्रोत है जो 2008-09 में लगभग 19 प्रतिशत था। चूंकि यूरो क्षेत्र में बेरोजगारी की स्थिति लगातार बिगड़ती रही है, अतः भारत को विप्रेषण प्रवाह में कमी आ सकती है।

**निष्कर्ष**

यूरो क्षेत्र का संकट कब तक चलेगा, इस बारे में अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि कई सारे नीतिगत उपाय किए जाने के बावजूद इसकी वास्तविक अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक सुधार नहीं आया है। इधर सुधार लागू किए जा रहे हैं और उधर नई चिंताएं उभर रही हैं। उदाहरण के लिए, इटली और फ्रांस दोनों की ही रेटिंग कम हुई है।

भारत में, वैश्विक अर्थव्यवस्था, विशेषकर यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में व्याप्त अनिश्चितताओं से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए पूर्व-सक्रियता बरती गई है। हमारी अर्थव्यवस्था में पूंजी प्रवाह में अस्थिरता आने से चालू खाते का बड़ा घाटा एक चुनौती बन गया है। इस संदर्भ में, आयातों में कमी लाने तथा पूंजी प्रवाह बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने कई नीतिगत कदम उठाए हैं।

हमारे आयातों की दो प्रमुख मद्देन तेल और स्वर्ण हैं। तेल के मूल्यों को लगातार बाजार-निर्धारित बनाया जा रहा है। यह आशा की जाती है कि इससे तेल के घरेलू उपयोग

में कमी आएगी। हाल में, स्वर्ण पर आयात शुल्क में वृद्धि की गई है तथा स्वर्ण की गिरवी पर बैंक वित्त को सीमित किया गया है। हमने इन्फ्लेशन इंडेक्स बांड भी शुरू किए हैं। मुद्रास्फीति से बचाव के लिए जिस सीमा तक इनमें निवेश किया जाता है, उस सीमा तक स्वर्ण की मांग में कमी लाने में सहायता मिलेगी। हमारे जैसी तेजी से वृद्धिशील अर्थव्यवस्था में इन उपायों के होते हुए भी आयात मांग ऊंची बनी रहेगी। अतः व्यापार अंतर को कम करने के लिए हमें निर्यातों को बढ़ाना होगा। लेकिन, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही हो तो निर्यातों में वृद्धि लाना कठिन काम है। फिर भी, ऐसे कदम उठाए गए हैं, जिनसे व्यापार को उभरते बाजारों की ओर मोड़ा जा सके। लेकिन, चालू खाते का घाटा ऊंचा बना हुआ है, जिसे पूंजी प्रवाहों के जरिये कम करना होगा।

पूंजी प्रवाह बढ़ाने के लिए जो नीतिगत कदम उठाए गये हैं, उनमें अनिवासी जमाराशियों तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारों पर ब्याज दरों का उदारीकरण, बुनियादी सुविधाओं संबंधी ऋणों में विदेशी संस्थागत निवेशों से संबंधित मानदंडों का औचित्य-निर्धारण तथा बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति शामिल हैं। सरकारी प्रतिभूतियों तथा कंपनी बांडों में विदेशी संस्थागत निवेश की क्षेत्रगत सीमा को बढ़ाया गया है।

सार रूप में, यह कहा जा सकता है कि जहां राष्ट्रीय प्राधिकारी यथावश्यक कदम उठा रहे हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी चाहिए कि वे संकट को फैलने से रोकने के लिए पूर्व-सक्रियता से सुझाव दें तथा वैश्विक आर्थिक स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए तत्पर कार्रवाई करें। इस संदर्भ में, यूरो क्षेत्र में संपूर्ण बैंकिंग यूनियन का तेजी से कार्यान्वयन तथा सम्मिलित विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस परिदृश्य में, हमारी अर्थव्यवस्थाओं को संकट फैलने से

उत्पन्न नकारात्मक घटनाओं का सामना करने के लिए तैयार रहने के साथ-साथ अपनी मजबूती बढ़ाने के लिए कड़े प्रयास करने चाहिए। भारत के लिए तत्काल चिंता का विषय चालू खाते के विद्यमान उंचे स्तर को कम करना है। मध्यावधि में, व्यापार को उभरती अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तरफ मोड़ने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनमें तेजी लानी होगी। इस संबंध में, सार्क क्षेत्र में वित्तीय एकीकरण तथा व्यापार की अधिक संभावनाएं मौजूद हैं, जिससे परस्पर सभी लाभान्वित होंगे।